International Journal of Arts, Humanities and Social Studies
www.socialstudiesjournal.com
Online ISSN: 2664-8660, Print ISSN: 2664-8652
Received: 04-01-2021, Accepted: 08-02-2021, Published: 12-02-2021
Volume 3, Issue 1, 2021, Page No. 31-33

भारत की पाकिस्तान नीतिः निरंतरता और बदलाव की आवश्यकता

दिनेश कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर, रक्षा अध्ययन विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय, तरावड़ी, करनाल, हरियाणा, भारत

DOI: https://doi.org/10.33545/26648652.2021.v3.i1a.56

सारांश
भारत के प्रति पाकिस्तान का दृष्टिकोण हमेशा सन्देहात्मक ही रहा है, भारत–पाक सम्बन्धों की कहानी भारतीय उपमहाद्वीप के दो बड़े देशों की विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक एवम सांस्कृतिक विचारधाराओं, समानताओं, विषमताओं, अर्न्तराष्ट्रीय दृष्टिकोण एवम् राष्ट्रीय हित्तों के साथ जुड़ी है, इसका फायदा बड़ी महाशक्तियों ने सैनिक अड्डो, द्वीपों तथा बन्दरगाहों के रूप में तलाश कर उठाया है क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश भारत से खत्तरे का हौव्वा खड़ा करके अमेरिका से आर्थिक सहायता प्राप्त करता रहा है, पाकिस्तान की विडम्बना सबसे बड़ी यही रही है कि वहां की फौज ने हमेशा ही वहां की सरकारों में अपना सीधा–2 व प्रत्यक्ष हस्तक्षेप किया है, यही पाकिस्तान की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण रहा है।

कूटशब्दः भारत की पाकिस्तान नीति, निरंतरता, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक

प्रस्तावना
भारत और पाकिस्तान के संबंध स्वभाव से ही प्रतिद्वंद्विता के रहे हैं। इसकी जड़ों में कट्टर भावना और मतभेद का इतिहास है। भारत का विभाजन हो या कश्मीर की समस्या, यहां तक कि 1965 और 1971 के युद्धों के कारणों पर भी, दोनों देशों का नजरिया भिन्न रहा है। आम पाकिस्तानी भी यह मान बैठा है कि सीमा पार से आतंक की समस्या इसलिए है कि भारत से पाकिस्तान को भारी खतरा है। दोनों देशों के बीच गहरे मतभेदों को दूर करने के लिए जरूरी है कि ऐतिहासिक तत्यों पर बातचीत हो और राजनीतिक कारणों से पैदा हुए विकृतियों को दूर रखा जाए।
पदभार संभालने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पड़ोसी देशों के प्रति नीति पर खास जोर दिया। पर क्या मोदी बातचीत की प्रक्रिया में बदलाव लाकर, भारत–पाकिस्तान संबंधों में मौजूद दुष्चक्र को तोड़ने में सफल रहे? भारत ने 2015 में पाकिस्तान के साथ संरचनात्मक वार्ताओं के लिए फिर पहल की। लेकिन, जनवरी 2016 में भारतीय वायुसेना के पठानकोट हवाई अड्डे पर आतंकी हमले ने फिर साबित कर दिया कि पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की प्रक्रिया का स्वरूप कितना नाजुक है। संशयवादियों का मानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 'कभी वार्ता–कभी बाधा–कभी वार्ता' का यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।
पठानकोट हमले के बाद इस बात पर बहस चल रही है कि भारत को क्या पाकिस्तान को काबू में रखने की नीति पर चलना चाहिए या उसके साथ शांति के लिए कोई व्यापक कार्ययोजना अपनानी चाहिए। अभी इस बहस का कोई खास असर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन, इस बात पर जोर देना जरूरी है कि सकारात्मक नतीजों के लिए यदि पाकिस्तान के साथ वार्ता को स्थिरता प्रदान करनी है तो पाकिस्तान से नई नीतियों के साथ व्यवहार करना होगा।
गत 2 जनवरी को सीमा पार से आए आत्मघाती आतंकियों के पठानकोट एयरबेस पर हमले से, यही दिखता है कि पाकिस्तान के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। कई लोगों का मानना था कि परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा कोई हमला अपेक्षित था। पाकिस्तान ने राजनीतिक नेतृत्व के शांति प्रयासों को कई बार ध्वस्त किया है। लेकिन, जो अपेक्षित नहीं था, वह था इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व की प्रतिक्रिया। क्रिसमस के मौके पर, मोदी की पाकिस्तान की अनपेक्षित यात्रा के एक सप्ताह बाद हुए इस हमले के बावजूद, सरकार ने जज्बाती होकर प्रतिक्रिया नहीं दी। भारत ने वार्ता का सिलसिला रोकने का फैसला नहीं किया बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने साथियों और अधिकारियों से संयम बरतने को कहा। भारत इस हमले के बाद पाकिस्तान की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करना चाहता था। पाकिस्तान ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की और भारत के आश्वासन दिया कि जो सबूत भारत पाकिस्तान को सौंपेगा, उन पर गंभीरता के साथ कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बात की। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ले. जनरल नसीर खान जंजुआ ने अपने समकक्ष अजीत डोभाल से बातचीत की। भले ही अतीत में पाकिस्तान के साथ बातचीत और व्यवहार के कोई खास नतीजे नहीं निकले हों, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में, पाकिस्तान के साथ बाचतीत के तौर–तरीकों में खास बदलाव लाने का अवसर खोजने की चेष्टा जरूर की। अपनी पार्टी के प्रभावी नेता होने, लोकसभा में भारी बहुमत और विश्व की बड़ी ताकतों के साथ मजबूत रिश्तों के कारण, मोदी को कामयाबी की गारंटी न होने के बावजूद, पाकिस्तान के साथ नए सिरे से बातचीत करने का जोखिम उठाने की ताकत हासिल थी।

मीडिया की भूमिका
कठोर औपचारिकताओं का प्रदर्शन करके जहां दोनों देशों की नौकरशाही ने शांति वार्ता को आघात पहुंचाया, वहीं भारतीय मीडिया ने दोनों देशों के बीच होने वाली वार्ता की किसी भी कोशिश की, इस तरह पेश किया मानो दो तलवारबाजों के बीच जंग छिड़ने वाली हो। मीडिया के इस आक्रामक तेवर के जवाब में मोदी को चाहिए कि वे इसकी अनदेखी करें और पाकिस्तान के साथ सामान्य रूप से बाचतीत जारी रखें। साथ ही सकारात्मक तत्वों के साथ समानांतर, निरंतर और संयम

के साथ संपर्क जारी रखा जाए। इसका अर्थ है कि वार्ताओं की शर्तों और मोलभाव पर आधारित नहीं बल्कि सतत राजयन की प्रक्रिया के रूप में आगे बढ़ाया जाए। वीजा नीति को उदार बनाते हुए दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना अन्य सकारात्मक कदमों में से एक हो सकता है। वर्ष 2004 से सीमित वीजा उदारीकरण के बावजूद दोनों देशों के लोगों का एक दूसरे के यहां आना जाना बढ़ा है। पाकिस्तान में लोगों की यह जबर्दस्त इच्छा है कि वे भारत की यात्रा करें। दोनों मुल्कों के बीच सांस्कृतिक समानताएं हैं। बॉलीवुड पाकिस्तान के लोगों के जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। जितने ज्यादा पाकिस्तानी भारत आएंगे, पाकिस्तान के उन तत्वों को भारत के खिलाफ बरगलाना उतना ही मुश्किल होता जाएगा जो दोनों देशों के रिश्ते बिगाड़ने को तैयार रहते हैं। नागरिक स्तर पर ही नहीं बल्कि सैन्य स्तर पर भी संपर्क बढ़ाना बेहतर रहेगा।

पाकिस्तान से व्यवहार करना एक चुनौती जरूर है लेकिन सोची समझी रणनीति के तहत यदि राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक साधनों का इस्तेमाल किया जाए तो पाकिस्तान के लोगों में, भारत की नीतियों को लेकर जो आशंकाएं रहती हैं, उन्हें दूर किया जा सकता है।

जब दोनों देश ये महसूस करते हों कि उनके रिश्ते संतोषजनक नहीं हैं, ऐसे में सोच में ठोस बदलाव लाना आवश्यक है। हर समाज की अपने को लेकर एक खास सोच होती है। भारत में सोच है कि पाकिस्तान की समस्या उसकी पहचान को लेकर है। इसलिए वह खुद को भारत का विरोधी बनकर परिभाषित करता है। लेकिन, पाकिस्तान की कई बार यात्रा करने के बाद ऐसा लगता है कि वहां के लोगों के मन में भारत को लेकर कोई ज्यादा कटुता नहीं है। वहां से आए लोग ऐसा ही कुछ भारत में महसूस करते हैं। बुद्धिजीवी या विश्लेषक कुछ भी कहें लेकिन अनुभव के आधार पर मुझे लगता है कि पाकिस्तानी जनता में अपनी पहचान को लेकर कोई खास समस्या नहीं है।

फौजी नेतृत्व के पास ही है असली ताकत

यह धारणा कि पाकिस्तान की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार भारत के साथ दोस्ती के पक्ष में है, पूरी तरह सही नहीं है। वहां हालात की जटिलता इतनी है कि नेता, नौकरशाह और फौज की तिकड़ी शासन चलतीी है। चाहे इसमें आपस में कितने ही मतभेद हों लेकिन ये तीनों भारत के बारे में गहरी नकारात्मक सोच रखते हैं। यह सोचना भारत के लोगों की भी खाम ख्याली होगी कि भारत पाकिस्तानी की घरेलू राजनीति को कुछ खास प्रभावित कर सकता है। पाकिस्तान में बदलाव वहां की आंतरिक ताकतें ही लाएंगी। पाकिस्तान में नागरिक–सैन्य संबंधों की विचित्र प्रकृति के कारण, यहां नागरिक सरकार के सत्ता में रहते भारत के लिए सैन्य नेतृत्व से बात करना कठिन हो जाता है। भारत के लिए पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व से संपर्क करना तभी संभव होता है जब वहां फौजी हुकूमत हो। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में 2003 और 2007 में भारत ने पाकिस्तान से संबंध सुधारने में काफी प्रगति की थी। वर्ष 2008 में आसिफ जरदारी की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सत्ता में आई और वह सरकार भी भारत के प्रति नरम रवैया अपनाना चाहती थी लेकिन तब फौज ने सरकार को भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाने की पूरी आजादी नहीं दी।

अक्तूबर 2015 में पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल नासिर खान जंजुआ की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में नियुक्ति हुई। उनमें भारत को मध्यस्थ की छवि नजर आई। जंजुआ को प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और फौजी जनरल राहिल शरीफ का समर्थन प्राप्त था। दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलहाकारों की बैंकॉक में बातचीत हुई जिसे बैंकॉक मेकेनिज्म कहा गया। लगता था इस मुलाकात के बाद कुछ सकारात्मक नतीजे निकलेंगे। लेकिन, पाकिस्तानी सेना भारत के प्रति शत्रुता के रवैये को खत्म करेगी, भारत में यह भरोसा किसी को नहीं था। मोदी और उनके सलाहकारों को सुनिश्चित करना होगा कि क्या जंजुआ एक भरोसेमंद संभाषी साबित होंगे जो पाकिस्तानी फौजी नेतृत्व को, भारत–पाक वार्ता में मदद करने को तैयार कर सके।

शांति प्रक्रिया और पाकिस्तान की कमजोर नब्ज

भारत में कई सामरिक विशेषज्ञ यह तक दे सकते हैं कि शांति प्रक्रिया किसी बड़े आतंकी हमले तक ही चलेगी। यदि भारत मुख्य मुद्दा आतंकवाद को मानता है तो पाकिस्तान, कश्मीर को मानता है। पाकिस्तान कश्मीरी अलगाववादियों का खुलकर समर्थन करता है और उनसे मुलाकातें करता है जो एनडीए सरकार को मजूंर नहीं। इसलिए अगस्त 2014 और 2015 में मोदी सरकार की शांति–वार्ता प्रक्रिया बाधित हुई। पाकिस्तान में फौजी शासनकाल में यानी 2004 और 2007 में, कश्मीर समेत कई मुद्दों पर अच्छी प्रगति हुई। इस बीच कुछ बड़ी आतंकी घटनाएं भी हुई लेकिन भारत ने शांति प्रक्रिया बाधित नहीं होने दी।

कश्मीर और आतंकवाद जैसे प्रमुख मुददे, एक–दूसरे से जुड़े हुए हैं। पठानकोट जैसे हमले और भी हो सकते हैं लेकिन 2016 में शुरू किया गया बैंकॉक मैकेनिज्म बढ़ाते हुए वार्ता रोकी नहीं जानी चाहिए लेकिन 2016 में शुरू किया गया बैंकॉक मैकेनिज्म बढ़ाते हुए वार्ता रोकी जानी चाहिए। किसी बड़े हमले के बाद भी, शांति प्रक्रिया जारी रहेगी या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आतंकवाद के खिलाफ, दोनों देशों के बीच सहयोग कितना मजबूत हुआ है। पाकिस्तान यह चाहेगा ही शांति प्रक्रिया किसी भी हाल में बंद न हो। मोदी सरकार के लिए मौका है कि शांति बहाली के लिए वह एकतरफा कार्यवाही करते हुए, 2007 के सिलसिले को आगे बढ़ाए। पाकिस्तान के मामले में तरीके बदलने की नहीं, बल्कि नई सोच की जरूरत है। दोनों देशों का भला इसी में है कि वे बातचीत की टेबल पर मसले सुलझाएं। भारत को चाहिए कि वह ऐसा बल प्रतिरोधी सिद्धांत तैयार करे जो पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दे कि यदि वह हमारी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का गलत फायदा उठाने की कोशिश करेगा तो उसे जवाबी कार्रवाई का सामना करना होगा। भारत के संसद भवन पर हमले सहित कई आतंकी हमलों के जवाब में ऑपरेशन पराक्रम (2001–02) छेड़ने जैसे फैसले ठीक नहीं होंगे क्योंकि ऐसे कदमों की कई कमजोरियां होती हैं। पाकिस्तान की ऐसी कई कमजोर नब्जें हैं जिन्हें हम जब चाहे दबा सकते हैं। गिलगित–बल्तिस्तान पर हमारा घोषित दावा है लेकिन शिमला समझौते के बाद हमने मजबूती से इस मांग को रखना तो दूर, खुलकर भी कुछ नहीं बोला। हम गिलगित–बल्तिस्तान के लोगों को अपने यहां बुलाने से भी कतराते हैं। हम उनके

मानवाधिकारों के हनन पर भी उनका साथ नहीं देते। बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के भयानक हनन पर हमारी चुप्पी बिल्कुल गैर वाजिब है।

भारत की पाकिस्तान नीति में स्पष्टता जरूरी

भारत ने पाकिस्तान से निपटने के लिए अलग–अलग वक्त पर, अलग–अलग नीति अपनाई। पूर्वी पाकिस्तान में पैदा हुए संकट में, हमने खुलकर भूमिका निभाई और बांग्लादेश का उदय हुआ। गुजराल सिद्धांत के रूप में हमने पाकिस्तान से अनुकूल रवैये की उम्मीद रखे बिना, शांति प्रक्रिया शुरू कर दी। इस लेख में यह बताने की कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की कट्टर हिन्दू राष्ट्रवादी सोच, पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने में रुकावट नहीं है बल्कि बड़ी रुकावट, पाकिस्तान के प्रति भारत की स्पष्ट नीति का न होना है।

हमारी नीति किसी घटना के बाद जवाब देने की रही है। आज पाकिस्तान के प्रति एक स्पष्ट नीति का होना बहुत जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान से रिश्ते सुधरने से भारत को वैश्विक ताकत के रूप में उभरने में मदद मिलेगी। कई सामरिक विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान एक नकारा मुल्क है और यह आतंकवाद का गढ़ है। लेकिन यह जानना जरूरी है कि पाकिस्तान एक मजबूत सैनिक व्यवस्था के काबू में है। नागरिक सरकार पर फौज की जकड़ कभी कम होगी, इसकी संभावना नहीं है। पाकिस्तान भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है।

पाकिस्तान में फौज का दबदबा इतना पुराना है कि वह वहां की राजनीति और सामाजिक सोच में गहरा रच–बस गया है। इसलिए भारत को, पाकिस्तानी फौज की वहां की जनता में स्वीकार्यता पर सवाल उठाना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान के प्रति भारत को ऐसी सोची–समझी रणनीति तैयार करनी चाहिए जो जरूरत पड़ने पर सख्त या नरम रवैया अपनाने में मददगार साबित हो। फौरी प्रतिक्रिया की नीति के बजाय मोदी सरकार को, सभी राजनीतिक दलों के साथ सलाह–मशवरे के बाद, पाकिस्तान को लेकर राष्ट्रीय सहमति वाली पॉलिसी बनानी चाहिए।

संदर्भ सूची

1. जगदीश प्रसाद वर्मा, 'पाकिस्तान का परमाणु अस्त्र कार्यक्रम : उद्देश्य एवं उत्प्रेरक'' डॉ. विजेन्द्र सिंह (सम्पा0) 'राष्ट्रीय सुरक्षा' विक्ट्री पब्लिकेशन, इलाहाबाद, 2010, पृष्ठ – 123, 124
2. सविता पाण्डेय 'पाकिस्तान न्यूक्लियर स्ट्रेटजी, जसजीत सिंह (सं0) एशियन स्ट्रेटजी रिव्यू, 1993–94, नई दिल्ली 1994, पृष्ठ–338
3. डॉ. सुरेन्द्र कुमार मिश्र (सम्पा0), भारतीय परमाणु नीति निःशस्त्रीकरण व अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2006, पृष्ठ संख्या – 98
4. अरुण पटवारी, 'पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्त्रातेजी का भारत की सुरक्षा के संदर्भ में विश्लेषण'', डॉ. सुरेन्द्र कुमार मिश्र (सं0), पूर्वोद्धत, पृष्ठ–94
5. डॉ. आर.एस. पाण्डेय एवं स्व. डॉ. बाबू राम पाण्डेय, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, प्रकाश बुक डिपो, बरेली, 2008, पृष्ठ 2
6. दैनिक जागरण, 25 अगस्त 2022
7. दैनिक जागरण, 14 मार्च 2021
8. सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, मई 2020
9. प्रो0 पुष्पेश पंत, स्कूल ऑफ इण्टरनेशनल स्टडीज, जे.एन.यू., दैनिक जागरण, 25 अगस्त 2013
10. डॉ. आर.एस. पाण्डेय, चीन की सामुद्रिक महत्वाकांक्षाएं एवं भारतीय सुरक्षा' एक मूल्यांकन प्रतियोगिता/जून/2020
11. डिफैन्स मॉनीटर दिसम्बर–जनवरी 2022